



समूह संपादक- डॉ. ओ.पी. मिश्रा

https://epaper.tamsasanket.com

लखनऊ व अम्बेडकर नगर से एक साथ प्रकाशित

डॉ. लोहिया की जन्म भूमि से सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र

मौसम
सूर्योदय: 05:42
सूर्यास्त: 06:31
अधिकतम: 39°00
न्यूनतम: 25°00



विशेष समाचार 2029 को लेकर अभी से डरे हुए... पेज 02 आशुतोष महाराज ने डिप्टी सीएम... पेज 04 मूत बंगला प्रमोट करने में हुई अक्षय...



सम्राट चौधरी संभालेंगे 29 मंत्रालय

जेडीयू के पास 18 विभाग, मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद सम्राट ने छुए नीतीश के पैर

तमसा संकेत, एजेंसी

पटना। सम्राट चौधरी बिहार के 24वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने ईश्वर के नाम पर शपथ ली। राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने लोकभवन में सुबह 11 बजे उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। बिहार की नई सरकार में जदयू से विजय चौधरी और बिजेन्द्र यादव ने भी शपथ ली। दोनों को डिप्टी CM बनाया गया है। नीतीश कुमार इस कार्यक्रम में मौजूद थे। बिहार में अभी मंत्रिमंडल का ऐलान नहीं किया गया है। सम्राट चौधरी के पास गृह समेत 29 विभाग रहेंगे। विजय चौधरी को 10 और बिजेन्द्र यादव को 8 विभाग मिले हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद यही विभाग बाकी मंत्रियों में बंटेंगे। तब तक तीनों मंत्री ही इनकी जिम्मेदारी संभालेंगे। मुख्यमंत्री के पिता शकुनी चौधरी ने कहा, 'कभी-कभी ईश्वर की कृपा होती है। हमने कई पार्टियों के लिए पूरी लड़ाई लड़ी, लेकिन सफलता नहीं मिली। आज अमित शाह, नरेंद्र मोदी और नीतीश की कृपा से सम्राट आगे बढ़ गया।

- शपथ से पहले सम्राट चौधरी ने सुबह पंचमुखी हनुमान मंदिर में पूजा की।
- शपथ लेने के बाद सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को हाथ जोड़कर प्रणाम किया।



पप्पू यादव बोले- बीजेपी की पूर्वा पर नीतीश मर्जी भारी

पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने सम्राट चौधरी को बिहार के सीएम बनने पर बधाई दी है। साथ ही बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व पर तंज कसा है। पप्पू यादव ने लिखा, "बिहार के नए CM और उनके सहयोगियों को शपथ एवं दायित्व ग्रहण की बहुत-बहुत बधाई। बिहार में BJP का पहले मुख्यमंत्री सम्राट जी बने हैं, लेकिन BJP में अजीब सनटाय पसर है। क्या नीतीश जी के कोटे से BJP के CM बने हैं? बीजेपी के सर्वोच्च नेताओं की पूर्वा पर नीतीश जी की मर्जी भारी पड़ गई।"

सीएम बनते ही सम्राट चौधरी के 5 बड़े निर्देश

1. दौगुनी गति से काम कर समस्याओं का तेजी से समाधान
2. अधिकारी राज्य से भ्रष्टाचार खत्म करने को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति पर दृढ़ता से काम करें
3. मुख्यमंत्री स्तर से नीचे स्तर तक कहीं भी कार्यों को लटकाने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए
4. प्रखंड और थाने में आम जनता को सुविधा मिले और समय से समस्याओं का समाधान हो
5. बिहार को विकसित और समृद्ध प्रदेश बनाने के लिए एकजुट होकर अनुशासन और सवेदनशीलता के साथ काम करें

दीपक प्रकाश बोले- नीतीश के तय लक्ष्य को पूरा करेगी नई सरकार

सम्राट चौधरी के शपथ ग्रहण पर मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा, "नई सरकार का गठन हो गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और नए उपमुख्यमंत्री को भी शुभकामनाएं और बधाई है। बिहार में जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम होता आया है, बिहार के लिए जो उन्होंने लक्ष्य तय किया था, निश्चित तौर पर सरकार और अधिक ऊर्जा के साथ उस लक्ष्य की प्राप्ति करेगी।"

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी ने कहा, "कभी-कभी ईश्वर की कृपा होती है। हमने पूरी लड़ाई लड़ी, लेकिन सफलता नहीं मिली। आज अमित शाह, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की कृपा से सम्राट आगे बढ़ गया। हर मेहनत रंग लाती है जो मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा।"

मैथिली ठाकुर बोलीं- नीतीश बिहार को जंगलराज से बाहर लाए

भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर ने कहा, आज बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन है। नीतीश कुमार बिहार को जंगलराज से निकालकर सुशासन के राज में लेकर आए हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए सम्राट चौधरी को बहुत-बहुत शुभकामनाएं। पहले भी NDA के मुख्यमंत्री थे आज भी NDA के मुख्यमंत्री हैं। शपथ के बाद सम्राट चौधरी सचिवालय पहुंचे। वहां उन्होंने अपना कामकाज संभाला। इसके बाद वे बीजेपी ऑफिस पहुंचे हैं।

पीएम मोदी ने सम्राट चौधरी को दी बधाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। उन्होंने X पर लिखा, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर सम्राट चौधरी जी को बहुत-बहुत बधाई और ढेरों शुभकामनाएं। उनकी ऊर्जा, जनसेवा के प्रति समर्पण और जमीनी अनुभव राज्य के लिए बेहद उपयोगी साबित होने वाला है।

फास्ट न्यूज

ट्रेन से कटकर 5 की मौत

प्रयागराज। प्रयागराज में बुधवार शाम करीब 7:30 बजे ट्रेन से कटकर 5 लोगों की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस और रेलवे की टीम मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के मुताबिक, मृतकों की पहचान कराना का प्रयास किया जा रहा है। हादसा करछना क्षेत्र का पचदेवरा हाल्ट का है।

जज के बच्चे सॉलिसिटर-जनरल के साथ काम करते हैं: केजरीवाल

नई दिल्ली। अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाला केस की सुनवाई कर रहे जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को फिर से घटाने की मांग की है। केजरीवाल ने बुधवार को जस्टिस कांता की अदालत में एक और हलफनामा दाखल किया है। इसमें केजरीवाल ने जज के दो बच्चों के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के साथ काम करने का मुद्दा उठाया है। केजरीवाल ने लिखा- जज के दोनों बच्चे तुषार मेहता के साथ काम करते हैं। तुषार मेहता उनके बच्चों को केस सौंपते हैं। तुषार मेहता CBI को तरफ से पेश होने वाले वकील हैं। ऐसे में, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा तुषार मेहता के खिलाफ आदेश कैसे जारी कर पाएंगी?

बिजली के एक झटके में जिंदा जला युवक

खजुराहो। मध्य प्रदेश के खजुराहो रेलवे स्टेशन के पास स्थित 'दि खजुराहो हेरिटेज रिसोर्ट' में एक कर्मचारी की करंट लगने से मौत हो गई। यह घटना मंगलवार शाम 6 बजे छत से बंदर भागते समय हुई। घटना का वीडियो बुधवार को सामने आया है। मृतक की पहचान खजुराहो निवासी रिकू रैकवार के रूप में हुई। उसने आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए पांच दिन पहले ही होटल में काम शुरू किया था।

अयप्पा मंदिर रेस्टोरेंट नहीं : सबरीमाला मैनेजमेंट

यहां ब्रह्मचारी देवता, महिलाएं क्यों आना चाहती हैं

सुनवाई

नई दिल्ली। केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में चौथे दिन सुनवाई हुई। मंदिर का मैनेजमेंट देखने वाले त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (TDB) ने कहा कि यह खिलाईने की दुकान या रेस्टोरेंट का मामला नहीं है। यह आज्ञा ब्रह्मचारी माने जाने वाले देवता का मंदिर है। TDB का पक्ष रखते हुए एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा- 10 से 50 साल के उम्र की महिलाएं देवता के स्वरूप और पहचान के विपरीत हैं। भारत में अयप्पा के लगभग 1,000 मंदिर हैं। अगर महिलाओं को दर्शन करना है, तो वहां जाएं। उन्हें इसी खास मंदिर में क्यों आना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि करोड़ों लोगों की आस्था को गलत ठहराना सबसे मुश्किल कामों में से एक है। साथ ही यह भी कहा कि सामाजिक सुधार के नाम पर धर्म को खोखला नहीं किया जा सकता। केरल हाईकोर्ट ने 1991 में सबरीमाला में 10 से 50 साल की महिलाओं की एंट्री पर बैन लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इसे भेदभावपूर्ण बताते हुए बैन हटा दिया। इस फैसले के खिलाफ कई पुनर्विचार याचिकाएं लगाई गईं।

कार्यवाही: गलत वीडियो पोस्ट कर माहौल बिगाड़ने का आरोप, 2 दिन बाद फैक्ट्रियां खुलीं, फोर्स तैनात

नोएडा बवाल : आरजेडी की 2 महिला प्रवक्ताओं पर एफआईआर

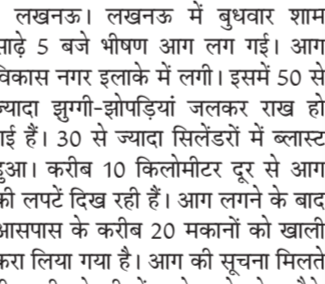
नोएडा। नोएडा में 2 दिन हुए बवाल के बाद आज यानी बुधवार को फैक्ट्रियां खुल गईं हैं। हालात सामान्य हैं। जगह-जगह फोर्स तैनात है। CCTV और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। 16 कंपनी RAF और पीएसी लगाई गई हैं। नोएडा सेक्टर 63, 84, 85, 80, फेस 2 में पुलिस ने फ्लेमोमार्च किया। कंपनियों के बाहर सैलरी हाईक के नोटिस चस्पा किए गए हैं। हालांकि, कुछ कंपनियों में आज छुट्टी कर दी गई है। कंपनियों ने बाहर नोटिस चिपकाकर कर्मचारियों को बताया गया कि आज कंपनी बंद रहेगी। कल के लिए सूचना आपको पहले से ही दी जा चुकी है। इस बीच, नोएडा साइबर क्राइम टीम ने 66 रुपम ने कहा- अगर कोई आउटसोर्सिंग एजेंसी या उसका कर्मचारी गड़बड़ी या उपद्रव करता है तो उसकी जिम्मेदारी एजेंसी की ही होगी। ऐसी स्थिति में एजेंसी को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। उसका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है।

50 से ज्यादा झोपड़ियां जलीं, 30 सिलेंडर फटे

युवक बोला- मेरे 4 बच्चे जिंदा जल गए, डिप्टी सीएम मौके पर पहुंचे

घटना

लखनऊ। लखनऊ में बुधवार शाम साढ़े 5 बजे भीषण आग लग गई। आग विकास नगर इलाके में लगी। इसमें 50 से ज्यादा झुग्गी-झोपड़ियां जलकर राख हो गईं हैं। 30 से ज्यादा सिलेंडरों में प्ल्यास्ट हुआ। करीब 10 किलोमीटर दूर से आग की लपटें दिख रही हैं। आग लगने के बाद आसपास के करीब 20 मकानों को खाली करा लिया गया है। आग की सूचना मिलते ही झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोग मौके पर पहुंचे हैं। एक युवक का कहना है कि उसके 4 बच्चों की जलकर मौत हो गई है। वहाँ, बाकी लोगों का सारा सामान जलकर राख हो गया है। चारों तरफ अफसोस-तफरोस का माहौल है। जिनकी झोपड़ियां जलीं हैं, वो लोग रो रहे हैं। बार-बार अपनी झोपड़ी में जाने की जिद कर रहे हैं। इलाके की लाइट काट दी गई है। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी हैं। सीएम योगी ने आग की घटना का संज्ञान लेते हुए अफसरो को तुरंत मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। कहा है कि राहत कार्य में तेजी लाई जाए।



विकास नगर झुग्गी-झोपड़ी में आग की सूचना मिलने के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौके पर पहुंचे। हालात का जायजा लिया और अधिकारियों से तेजी से बचाव कार्य करने के आदेश दिए। ब्रजेश पाठक ने कहा- भयावह आग लगी है।



डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौके पर पहुंचे और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने, घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहित करने, रसायन-मुक्त प्राकृतिक खेली अयनाने, मोटे अनाज (मिलेट्स) के साथ स्वस्थ भोजन को बढ़ावा देने और तेल के कम उपयोग की अपील भी की। पीएम मांड्या जिले के श्री क्षेत्र आदिचुंचन-गिरि मठ पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने गुरु भैरवक्य मंदिर का उद्घाटन किया। सौंदर्य लहरी और शिव महिम्न स्तोत्र नामक किताब का विमोचन भी किया। इस मौके पर पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा भी मौजूद थे। यह चोक्कालिया समुदाय से जुड़ा है।

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले- बहुत भयावह घटना

विकास नगर झुग्गी-झोपड़ी में आग की सूचना मिलने के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौके पर पहुंचे। हालात का जायजा लिया और अधिकारियों से तेजी से बचाव कार्य करने के आदेश दिए। ब्रजेश पाठक ने कहा- भयावह आग लगी है।

नालियों में फेंके गए गैस सिलेंडर

आग लगने के बाद लोगों ने झोपड़ियों में रखे सिलेंडर नालियों में फेंक दिए। जिससे वो फटने न पाए। अभी भी दर्जनों गैस सिलेंडर नालियों में पड़े हैं। आग लगने से रोड पूरी तरह से जाम हो गया है। मुंशी पुलिया से लेकर इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा और फ्लाइंगोवर पर लोग घंटों से जाम में फंसे हैं। दरअसल, झुग्गी-झोपड़ी में आग लगने के बाद अवानक बढ़ी फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की आवाजाही बंद गई। इससे मेन रोड पर जाम लगा गया।

प्लांट के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न हो: योगी

मुख्यमंत्री ने टाटा प्लांट में 10 लाखवीं बस को किया प्लेग ऑफ

लॉन्च

लखनऊ में टाटा मोटर्स प्लांट में 10 लाख गाड़ियां बन चुकी हैं। बुधवार को सीएम योगी ने 10 लाखवीं गाड़ी (ई-बस) को हरी झंडी दिखाई। उसमें बैठे भी। इस दौरान टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन ने उन्हें गाड़ी की खासियत बताई। सीएम ने कहा- 10 लाखवां वाहन का उत्पादन सिर्फ एक औद्योगिक उपलब्धि नहीं, ऐतिहासिक उड़ान का लॉन्च पैड है। यह उस नए युगी का प्रतीक है, जो देश के सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य को ग्लोबल मैनुफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। विश्वास के साथ कहता हूँ कि



योगी आदिनाथ ने गोल्फ कोर्ट में सवार होकर प्लांट में विजिट किया। टाटा मोटर्स की 10 लाखवीं गाड़ी को देखकर सीएम योगी ने ताली बजाई। यह उड़ान रुकने वाली नहीं, बल्कि और अधिक ऊंचाइयां छुएंगी।

सम्पादकीय

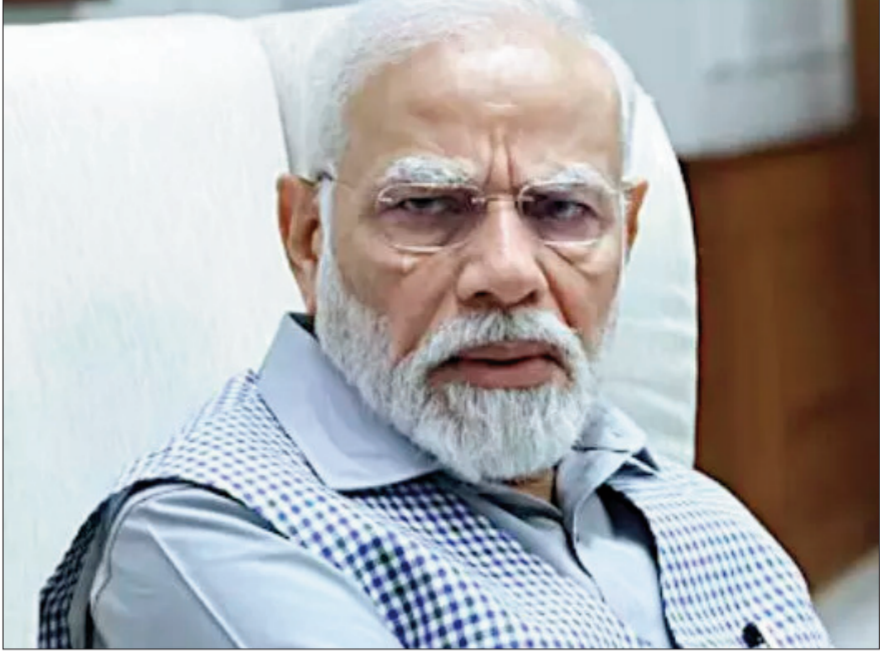
मजदूरों के गुस्से का पाकिस्तान और नक्सली लिंक



मई दिवस या अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस आने में अभी एक पखवाड़े का वक्त बचा है, लेकिन जिन वजहों से 140 साल पहले मजदूरों ने अपनी आवाज़ बुलंद की थी, वो वजहें अब कई गुना सघनता के साथ समाज में मौजूद हैं। इसकी झलक सोमवार और मंगलवार को उत्तरप्रदेश के औद्योगिक नगर नोएडा में दिखाई दी। वही नोएडा जहाँ कुछ दिनों पहले जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया और कहा कि अब युवाओं के विकास की उड़ान को पंख मिलेंगे। दिल्ली से सटे नोएडा में कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दफ्तर और कारखाने हैं। आलीशान रिहायशी इलाके हैं, जहाँ करोड़ों के फ्लैटों और कोठियों में समाज का उच्च तबका रहता है। लेकिन इस चमकमताती दुनिया के पीछे वही मलिन बस्तियाँ हैं, जिन्हें छिपाने के लिए अक्सर सफेद पर्दे डाल दिए जाते हैं। याद कीजिए अहमदाबाद में नमस्ते ट्रेप से लेकर दिल्ली में जी-20 की बैठक तक जब भी अंतरराष्ट्रीय मेहमान भारत आए, ऐसे ही गरीबी को छिपाया जाता रहा। लेकिन सोमवार 13 अप्रैल को नोएडा के फेज टू में एक निजी कंपनी के श्रमिकों ने काम के घंटे और मेहनताने को लेकर जो प्रदर्शन किया, वह छिपाया नहीं जा सका। चूँकि कई बड़े चैनलों के दफ्तर नोएडा में ही हैं, तो यहाँ मजदूरों के बढ़ते असंतोष और उसे दबाने के लिए कई प्रशासनिक सख्ती को पूरा करवने मिला। हालाँकि नोएडा से पहले कई और शहरों में मजदूरों की नाराजगी सामने आई है। इस साल फरवरी में बिहार के बरौनी में मजदूर न्यूनतम वेतन बढ़ाने और काम के घंटे तय करने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे। इसके बाद सूदूर, मानेसर, पानीपत और फिर नोएडा तक यह सिलसिला फैल गया। इन सभी जगहों पर मांगें लगभग एक जैसी थीं- न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी, ओवरटाइम का सही भुगतान, बकाया राशि का निपटारा और स्थायी कर्मचारियों जैसी सुविधाएँ। मजदूर संगठनों का कहना है कि नवंबर 2025 में लागू हुए नयी श्रमिक संहिता के बाद मजदूरों को उम्मीद थी कि उनकी स्थिति बेहतर होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नोएडा का विरोध प्रदर्शन खास तौर पर इसलिए व्यापक हो गया क्योंकि वहाँ बड़ी संख्या में टेका मजदूर काम करते हैं। ये मजदूर टेकेदारों के जरिए रखे गए हैं और उन्हें न तो स्थायी नौकरी की सुरक्षा है और न ही पीएफ या अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ मिलती हैं। 8 अप्रैल से ही मजदूरों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था जो धीरे-धीरे तेज हुआ और सोमवार को यह हिंसक हो गया। ट्रेड यूनियन नेताओं का आरोप है कि पिछले पांच दिनों से उन्हें नजरबंद रखा गया था, जिससे हालात और बिगड़ गए। उनका कहना था कि जब मजदूरों से बातचीत ही नहीं होगी, तो स्थिति नियंत्रण से बाहर होनी ही थी। मजदूर वर्ग की ऐसी नाराजगी किसी भी सत्ता के लिए चेतानेवाली होती है कि उसकी नीतियों से जनता संतुष्ट नहीं है, लिहाजा उसे आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। लेकिन मौजूदा भाजपा के शासनकाल में सत्ता से नाराजगी सीधे देश से विद्रोह मान लिया जाता है। जब किसान आंदोलन हुआ था तो उसे खालिस्तानी आतंकवाद से जोड़ा गया था। शाहीन बाग आंदोलन में अंतरराष्ट्रीय साजिश देखी गई। और अब नोएडा में मजदूरों के विरोध प्रदर्शन में पाकिस्तान और नक्सलवाद का कोण सरकार ने ढूँढ निकाला है। उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री अनिल राजभर ने मजदूरों की जाजिब मांग को 'बड़ी साजिश' का हिस्सा बताया और कहा कि इसमें 'पाकिस्तान लिंक' की भी जांच की जा रही है। वहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बयान दिया कि यह 'नक्सलवाद को फिर से जीवित करने की साजिश' का हिस्सा हो सकता है। उन्होंने अधिकारियों को सतर्क रहने और 'विघ्नकारी तत्वों' की पहचान करने के निर्देश दिए हैं। कितनी चालाकी से सरकार ने अपनी जिम्मेदारी पाकिस्तान और नक्सलवाद पर डालने की कोशिश की, हालाँकि बाद में सरकार ने औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति गठित की, जिसे मजदूरों और उद्योगों के बीच बातचीत कर समाधान निकालने का जिम्मा दिया गया। अब सरकार ने न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की घोषणा की है। नोएडा (गौतम बुद्ध नगर) और गाजियाबाद में अब अकुशल मजदूर को 13,690 रुपये, अर्ध-कुशल को 15,059 रुपये और कुशल मजदूर को 16,868 रुपये मासिक वेतन तय किया गया है। अन्य नगर निगम क्षेत्रों और बाकी जिलों में भी इसी तरह अलग-अलग दरें तय की गई हैं। सरकार ने वेतन बढ़ोतरी को 'संतुलित कदम' बताया है। लेकिन मजदूरों की शुरुआती मांगों और उनकी वास्तविक आय-व्यय की स्थिति को देखते हुए यह सवाल बना हुआ है कि क्या यह बढ़ोतरी उनके जीवन स्तर में वास्तविक सुधार ला पाएगी? बता दें कि नोएडा की फैक्ट्रियों में औसत वेतन 10-15 हजार रुपये के बीच है, जो बढ़ती महंगाई, खासकर मौजूदा ऊर्जा संकट के बाद, जीवनयापन के लिए पर्याप्त नहीं है। क्योंकि मजदूरों का वेतन तो वहीं का वहीं है, लेकिन इस बीच खाद्य सामग्री, शिक्षा, इलाज और क्रियाय सबकी कीमतें बढ़ गई हैं। बहुत से मजदूर इसी वजह से गांवों में वापस लौट गए हैं, हालाँकि वहाँ भी उनके लिए खेती-किसानी बची नहीं है। मजदूरों का कहना है कि भत्तों में बढ़ोतरी से बचने के लिए कर्मचारियों को नौ महीने के भीतर ही बर्खास्त कर दिया जाता है और फिर से नियुक्त कर लिया जाता है। उन्हें डर है कि कारखाना मालिकों ने सरकार के दबाव में न्यूनतम वेतन बढ़ाने की मांग मान तो ली है।

रमेश ने इस बात पर भी सवाल उठाया कि कैसे सरकार कह रही है कि परिसीमन के बाद उत्तर भारत के राज्यों का दबदबा नहीं बढ़ेगा और दक्षिण के राज्यों का असर कम नहीं होगा? उन्होंने इसके लिए केरल की मिसाल दी और कहा कि केरल व उत्तर प्रदेश के बीच अभी 60 लोकसभा सीटों का फर्क है, जो परिसीमन के बाद 90 सीटों का हो जाएगा।

2029 को लेकर अभी से डरे हुए हैं मोदी



कांग्रेस की ओर से पार्टी के संचार विभाग के प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके परिसीमन के प्रस्ताव पर सवाल उठाया। रमेश ने कहा कि महिला आरक्षण और परिसीमन का मामला व्यापक रूप से ध्यान भटकाने की योजना का हिस्सा है। रमेश ने इस बात पर भी सवाल उठाया कि कैसे सरकार कह रही है कि परिसीमन के बाद उत्तर भारत के राज्यों का दबदबा नहीं बढ़ेगा और दक्षिण के राज्यों का असर कम नहीं होगा? लोकसभा चुनाव- 2024 के नतीजों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनकी पार्टी का आत्मविश्वास बुरी तरह हिला रखा है। यद्यपि चुनाव आयोग बिल्कुल उनके मनमौफिक काम कर रहा है और ऐसा करते हुए वह निष्पक्ष रहना तो दूर, निष्पक्ष होने का दिखावा तक नहीं कर रहा है। उसकी तमाम असंवैधानिक और अनैतिक कारगुजारियों को न्यायपालिका की भी पूरा-पूरा संरक्षण मिला हुआ है। कॉरपोरेट नियंत्रित मीडिया भी पूरी तरह से सरकार और भाजपा के प्रचार तंत्र का हिस्सा बना हुआ है। इसी सबके चलते भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली और बिहार के विधानसभा चुनाव में अप्रत्याशित जीतें हासिल की हैं। इसके बावजूद 2029 के लोकसभा चुनाव को लेकर मोदी बेहद डरे हुए हैं। उनका यह डर लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण 2029 से ही लागू कराने और 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन कराने को लेकर उनकी हड़बड़ी में साफ देखा जा सकता है। दरअसल तमाम मोर्चों पर अपनी सरकार की नाकामियों के बावजूद 2019 के लोकसभा चुनाव और उसके बाद हुए कई विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत ने मोदी में इतना आत्मविश्वास पर दिया था कि उन्होंने 2024 के चुनाव में 'अबकी बार 400 पार' का नारा दे दिया था। वे मानकर चल रहे थे उन्हें 400 सीटों का बहुमत मिल ही जाएगा। उनके इसी आत्मविश्वास के बूते वे खुद तो नहीं लेकिन उनकी पार्टी के दूसरे कई वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री खुलेआम संविधान बदलने और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बातें करने लगे थे, जिसे मोदी भी नकार नहीं रहे थे। मगर उनकी तमाम तिकड़मों और चुनाव आयोग द्वारा की

गई गड़बड़ियों के बावजूद चुनावी परिणाम उनकी उम्मीदों के विपरीत आए। लोकसभा चुनाव 2014 में मिली 282 और 2019 में मिली 303 सीटों के मुकाबले 2024 में भाजपा जैसे-तैसे 240 सीटें ही जीतने में कामयाब रही। यानी बहुमत से बहुत दूर। मोदी खुद वाराणसी में जैसे-तैसे जीत पाए। करीब दो दर्जन पार्टियों के बने उनके गठबंधन (एनडीए) को भी कुल मिलाकर 292 सीटें ही हासिल हो सकीं, जो कि स्पष्ट बहुमत के आंकड़े से महज 20 सीटें अधिक रही। कुल मिला कर जैसे-तैसे सरकार चलाने लायक बहुमत मिला। ऐसे में संविधान बदलने या उसमें कोई भी मरामना संशोधन करने का उनका मंसूबा धरा रह गया। बस, यही स्थिति मोदी के लिए भविष्य में होने वाले चुनावों और खास कर 2029 के लोकसभा चुनाव को लेकर चिंता का सबब बन गई। यही नहीं, उन्हें विभाजनकारी और धार्मिक नारों की सीमाएँ भी समझ में आ गई कि अब इनका और ज्यादा दोहन नहीं किया जा सकता। कई छोटे-छोटे दलों के

समर्थन रूपी बैसाखियों के सहारे तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मोदी ने भविष्य में होने वाले चुनावों को जीतने की योजना पर काम करना शुरू किया। इस योजना के तहत चुनाव से ठीक पहले कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर मतदाताओं के खাতে में सरकारी खजाने से नकद राशि ट्रांसफर करने की योजनाएँ घोषित हुईं और जिनकी किस्तें चुनाव के दौरान जारी हुईं। ऐसा करना आदर्श चुनाव आचार संहिता के सरासर खिलाफ था, लेकिन चुनाव आयोग मुकदरशाक बना रहा। इस योजना को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई लेकिन न्यायपालिका ने भी इस अनैतिक हथकंडे पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। इसके अलावा महाराष्ट्र और हरियाणा में मतदान और मतगणना में भी चुनाव आयोग ने बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों को अंजाम देकर भाजपा की जीत का रास्ता साफ किया था। महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनाव जीतने के बाद मतदाताओं के खাতে में नकद राशि ट्रांसफर करने की योजना बिहार

में भी लागू की गई। इसके अलावा चुनाव आयोग के माध्यम से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के नाम पर जीत सुनिश्चित करने वाली एक नई योजना भी शुरू की गई, जिसकी शुरुआत दिल्ली से हुई और बाद में बिहार में भी लागू की गई। दोनों राज्यों में चुनाव आयोग ने एसआईआर के बहाने मनमाने तरीके से लोगों के नाम मतदाता सूचियों से हटाए, जिससे दोनों राज्यों में भाजपा और उसके गठबंधन को आसानी से जीत हासिल हो गई। बिहार और दिल्ली में कामयाबी के बाद एसआईआर के इतिहास को अभी हो रहे चुनाव वाले राज्यों तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल और पुद्दुचेरी सहित नौ राज्यों में भी आजमाया गया और हर राज्य में चुनाव आयोग ने मनमाने तरीके से लाखों लोगों के नाम मतदाता सूचियों से हटा दिए हैं। अलबत्ता असम को इस योजना से मुक्त रखा गया। जाने-माने अर्थशास्त्री डॉ. पराकला प्रभाकर ने, जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के पीछे हैं, क्षेत्र विशेष और वर्ग विशेष के मतदाताओं के नाम मतदाता सूचियों से हटाने की चुनाव आयोग की रातो-रात 'नाम मिटाओ, नाम चढ़ाओ और चुनाव जिताने परियोजना' को दुनिया का सबसे बड़ा रक्तहीन राजनीतिक जनसंहार करार दिया है। राजनीतिक विश्लेषण सेवा बहरहाल, प्रधानमंत्री को इतने से भी संतोष नहीं है। वे 2029 के चुनाव को लेकर कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसलिए वे 2029 के बाद लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने वाले नारी शक्ति वंदन कानून और लोकसभा व विधानसभा की सीटों के परिसीमन को भी 2029 के चुनाव से ही लागू करने की हड़बड़ी दिखा रहे हैं। हालाँकि यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि दोनों मामले संविधान संशोधन से जुड़े हुए हैं और संविधान संशोधन के लिए जरूरी दो तिहाई बहुमत सरकार के पास नहीं है। पहले ऐसा लग रहा था कि महिला आरक्षण और परिसीमन को लेकर विपक्षी दल दुविधा में है और उनके लिए इसका विरोध करना आसान नहीं होगा। लेकिन अब धीरे-धीरे विपक्ष दलों ने अपना रुख स्पष्ट करना शुरू कर दिया है।

अनिल जैन

यदि वर्षा सामान्य ...



जयसिंह रावत

कमजोर मानसून की आशंका: किसानों और अर्थव्यवस्था के सामने नई चुनौती

देश में वर्ष 2026 के दक्षिण-पश्चिम मानसून को लेकर जारी पूर्वानुमानों ने विशेष रूप से पहाड़ी राज्यों के लिए चिंता बढ़ा दी है। मौसम विभाग के दीर्घकालिक आकलन के अनुसार उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बड़े हिस्सों में इस वर्ष सामान्य से कम वर्षा होने की आशंका है। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में भी वर्षा सामान्य से कम रहने का अनुमान बताया गया है, जबकि लद्दाख में सामान्य से अधिक वर्षा हो सकती है। यह स्थिति केवल जलवायु की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि कृषि, जल संसाधनों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए भी गंभीर प्रभाव डाल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार, इस वर्ष देश में कुल मानसूनी वर्षा दीर्घकालिक औसत (एलपीए) का लगभग 92 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो सामान्य श्रेणी से नीचे की स्थिति को दर्शाता है। विशेष रूप से उत्तराखंड में सामान्य से कम वर्षा की संभावना 35 से 65 प्रतिशत के बीच बताई गई है। यह संकेत करता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में जल स्रोतों, सिंचाई और पेयजल व्यवस्था पर दबाव बढ़ सकता है। इस वर्ष कमजोर मानसून की आशंका के पीछे एक प्रमुख कारण उत्तरी गोलार्ध में सर्दी और वसंत ऋतु के दौरान हिम आवरण (स्नो कवर) का सामान्य से कम रहना बताया गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार, हिम आवरण का क्षेत्रफल कम होने से भूमि और वायुमंडल के बीच तापमान का अंतर कमजोर पड़ जाता है। यह अंतर मानसूनी की गति और उसकी तीव्रता को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब यह तापीय अंतर कम हो जाता है, तो मानसूनी हवाओं की शक्ति भी कमजोर पड़ सकती है, जिससे वर्षा की मात्रा प्रभावित होती है। वैश्विक जलवायु संकेतक भी इस वर्ष मानसून पर प्रभाव डाल सकते हैं। वर्तमान में ला-नीना की कमजोर होती स्थिति के कारण जलवायु तटस्थ अवस्था की ओर बढ़ रही है, जबकि मानसून के महीनों के दौरान अल-नीनो की संभावना जताई जा



रही है। अल-नीनो की स्थिति आमतौर पर भारत में वर्षा की कमी से जुड़ी होती है, क्योंकि इसके दौरान प्रशांत महासागर का तापमान बढ़ जाता है और मानसूनी हवाओं की दिशा व गति प्रभावित होती है। हालाँकि, वैज्ञानिकों का मानना है कि बाद के महीनों में हिंद महासागर द्विध्रुव (आर्कओडी) की स्थिति सकारात्मक हो सकती है जिससे वर्षा की कमी को आंशिक रूप से संतुलित किया जा सकता है। पहाड़ी राज्यों के लिए यह स्थिति विशेष रूप से संवेदनशील मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ मानसून वर्षा जल संसाधनों, कृषि और जलविद्युत उत्पादन का प्रमुख आधार है। उत्तराखंड और हिमाचल जैसे राज्यों में नदियों का प्रवाह, जलाशयों का स्तर और सिंचाई व्यवस्था काफी हद तक मानसून पर निर्भर रहती है। यदि वर्षा सामान्य से कम रहती है, तो इससे जलविद्युत परियोजनाओं के उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही, असमान वर्षा की स्थिति में भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं का खतरा भी बढ़ जाता है क्योंकि कभी-कभी कम कुल वर्षा के बावजूद अचानक तेज वर्षा की घटनाएँ अधिक नुकसान पहुंचा सकती हैं। देश की अर्थव्यवस्था पर भी कमजोर मानसून का असर पड़ना स्वाभाविक है। यद्यपि

विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान परिस्थितियों में भारत की समग्र अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर नहीं है कि वह पूरी तरह संकट में आ जाए, फिर भी कृषि क्षेत्र पर इसका सीधा प्रभाव पड़ सकता है। देश की सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान अभी भी लगभग एक-चौथाई के आसपास है, और यह क्षेत्र मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर है। भारत में लगभग 70 प्रतिशत कृषि भूमि को आवश्यक नमी मानसून से ही प्राप्त होती है। कई राज्यों में तो आधे से अधिक खेत वर्षा आधरित हैं। कमजोर मानसून का सबसे अधिक प्रभाव छोटे और सीमांत किसानों पर पड़ता है। उदाहरण के लिए, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में गेहूँ की लगभग आधी खेती वर्षा पर निर्भर है जबकि महाराष्ट्र में वर्षा आधारित खेती का अनुपात 80 प्रतिशत तक पहुँच जाता है। अल-नीनो के वर्षों में दालों का उत्पादन अक्सर घट जाता है, कभी-कभी यह गिरावट 25 प्रतिशत से अधिक तक पहुँच जाती है। इसका सीधा असर देश की खाद्य सुरक्षा और बाजार में कीमतों पर पड़ सकता है। जल संसाधनों पर दबाव बढ़ने का एक और कारण भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन है। जब वर्षा कम होती है, तो किसान दृश्यजल और पंपसेट का अधिक उपयोग करते हैं जिससे भूजल स्तर तेजी से नीचे चला जाता है। इसके साथ ही जलाशयों में पानी की उपलब्धता भी घट जाती है, जिससे सिंचाई और बिजली उत्पादन दोनों प्रभावित होते हैं। इस वर्ष स्थिति को और जटिल बनाने वाले कुछ अतिरिक्त कारक भी सामने आए हैं। मार्च और अप्रैल में हुई असाधारण वर्षा ने देश के कई हिस्सों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुँचाया है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति पहले से ही कमजोर हुई है। इसके अतिरिक्त, पश्चिम एशिया में जारी तनाव अचानक तेज वर्षा की घटनाएँ अधिक नुकसान पहुंचा सकती हैं। देश की अर्थव्यवस्था पर भी कमजोर मानसून का असर पड़ना स्वाभाविक है। यद्यपि

बिहार के आर्थिक...



कमलेश पांडेय

बिहार में विकास सम्बन्धी चुनौतियों को अवसरों में बदलना होगा सम्राट चौधरी को!

बिहार के नए सम्राट को फूलों की सेज नहीं, बल्कि कांटों का ताज मिला है। चाहे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हों या पूर्व मुख्यमंत्री दम्पति लालू प्रसाद हों या पूर्व मुख्यमंत्री कभी भी चैन पूर्वक राज नहीं कर सके। लिहाजा, मौजूदा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भी उन जातीय और साम्प्रदायिक चुनौतियों से जूझना होगा जो बिहार के विकास में शुरू से ही बाधक समझी गई हैं लेकिन जिस प्रकार से आधुनिक बिहार के निर्माता और प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिन्हा को कांग्रेस के सहयोग से लंबे समय तक राज करते हुए जनसेवा का मौका मिला, वैसी ही मौजूदा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भाजपा के सहयोग से जनसेवा का मौका मिला। उन्होंने कहा है कि पार्टी ने उन्हें पद नहीं, जनसेवा का अवसर दिया है, इसलिए विकास, सुशासन और समृद्धि उनके शासन का मूलमंत्र होगा। बिहार के आर्थिक विश्लेषण बताते हैं कि बिहार के विकास में श्रीकृष्ण सिन्हा के बाद नीतीश कुमार ने एक बड़ी रेखा खींचने की कोशिश की, प्रतिगति नारी भी आई लेकिन महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश और हाल के वर्षों में उत्तरप्रदेश के विकास को देखा जाए तो अब भी बिहार के विकास में कई बड़ी-बड़ी चुनौतियाँ बाकी हैं, जो आंकड़ों और राज्य की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को देखने पर साफ दिखती हैं। इसलिए भाजपा की सरकार के सुलझे हुए और अल्पसंख्यक प्रवृत्ति वाले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भी बिहार के समग्र विकास के लिए निम्नलिखित चुनौतियों से जूझना होगा लेकिन अपने मूठ स्वभाव से वे एक एक करके इनसे पार या जाएंगे, ऐसा मुझे दृढ़ विश्वास है। आंकड़े बताते हैं कि बिहार, भारत के सबसे कम आय वाले राज्यों में शुमार है, जहाँ गरीबी दर अभी भी काफी ऊँची है और रोजगार की गुणवत्ता कमजोर है। समझा जाता है कि शिक्षा



और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश कम होने के कारण यहाँ की 'मानव-पूंजी' कमजोर है-साक्षरता और स्किल लेवल अभी भी देश के स्तर से काफी नीचे हैं, जिससे युवाओं को अच्छे रोजगार के अवसर मिलने में दिक्कत होती है। ऐसे में यदि अपराध, जातीय सोच और सांप्रदायिक मिजाज को हतोत्साहित करके इन लक्ष्यों को पाया जा सकता है। इसके लिए अप्रवासी विहारियों और बिहार मूल के एन-आरआई को आकर्षित करने वाली योजनाओं को बनाना होगा और उनपर दृढ़तापूर्वक अमल करना होगा। यद्यपि हार की आबादी का वड़ा हिस्सा अभी भी आर्य पर निर्भर है लेकिन उत्पादकता और आय दोनों ही अपेक्षाकृत कम हैं। ऐसा इसलिए कि उत्तर बिहार 4 महीना बाढ़ से आर्तार्त रहता है और तभी दक्षिण बिहार सूखा से जूझ रहा होता है। खेती और बागवानी यहाँ पर होती तो है, लेकिन भंडारण सुविधाएँ, बाढ़-प्रबंधन, सिंचाई व्यवस्था जलवायु परिवर्तन और बारहमासी सिंचाई की सीमित पहुँच जैसे कारकों के कारण कृषि अभी भी बहुत जोखिम भरी और कम-लाभ वाली कार साबित होती है। लिहाजा किसानों को मजदूरों के बच्चे परदेश कमाने चले जाते हैं और अपनी उद्यमिता से सबको सुख पहुंचाते हैं। बिहार में 26 साल पहले हुए राज्य विभाजन के बाद औद्योगिक आधार छोटा हुआ है, क्योंकि अधिकांश बड़े उद्योग-धंधे झारखंड के हिस्से में चले गए।

जरा हटके

सुप्रीम कोर्ट ने...



डॉ ब्रजेश कुमार मिश्र

नारी शक्ति वन्दन अधिनियम: प्रतिनिधित्व और क्रियान्वयन की चुनौती

कामायनी के श्रद्धा सगं में जयशंकर प्रसाद ने नारी की चेतना को इंगित करते हुए लिखा है "नारी, तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास-रजत-नग-पाग वल में, पीयूष-स्रोत सी बहा कर, जेवना के सुन्दर समतल में।" अर्थात् नारी केवल एक व्यक्तिव नहीं, बल्कि श्रद्धा, विश्वास और जीवनदायिनी शक्ति का प्रतीक है, जो अपने स्नेह, करुणा और संवेदनशीलता से जीवन को सुन्दर और सन्तुलित बनाती है। भारतीय समाज में नारी सदैव आदरणीय रही है किन्तु यह भी एक कटु सत्य है कि इन आदर्शों के बावजूद वास्तविक सामाजिक और राजनीतिक जीवन में उसकी भागीदारी लम्बे समय तक सीमित रही है। यही विरोधाभास भारतीय लोकतन्त्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जहाँ एक ओर संविधान ने समानता का अधिकार प्रदान किया, वहीं दूसरी ओर संसद और विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत बहुत कम बना रहा जबकि

दुनिया के कई देशों जैसे बांग्लादेश (14%), पाकिस्तान (17%) औरनेपाल (33%) में महिलाओं के लिए संसद में आरक्षण है। इसी तरहवांडा (30%), तंजानियाऔरयूगांडामें भी विशेष आरक्षण अथवा कोटा व्यवस्था लागू है। ऐसे परिप्रेक्ष्य में महिला आरक्षण अधिनियम, 2023 (नारी शक्ति वन्दन अधिनियम)इस ऐतिहासिक असन्तुलन को दूर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और बहुप्रतीक्षित पहल के रूप में सामने आया। 28 सितम्बर 2023 को कानून बनने के बाद मध्य प्रदेश,राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम विधानसभाओं के चुनाव हो चुके हैं फिर भी यह अपनी मूलता की बात जोह रहा है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए सरकार 16-18 अप्रैल के मध्य संसद का विशेष सत्र बुला रही है, लेकिन सवाल यह है कि अब तक सरकार ने इस सन्दर्भ में प्रयास क्यों नहीं किया, सरकार की अग्रिम योजना क्या है और इस कानून



के लागू हो जाने के बाद क्या बदलाव होगा, ये ऐसे गूढ़ प्रश्न हैं जिन्हें संवैधानिक और व्यावहारिक पहलुओं के आलोक में समझा जा सकता है। यदि हम इस प्रश्न की जड़ों में जाएँ, तो असमान प्रतिनिधित्व की समस्या नष्ट नहीं है।संविधान सभा, जिसने स्वतन्त्र भारत के लोकतान्त्रिक ढाँचे की रचना की, उसमें भी महिलाओं की भागीदारी अत्यन्त सीमित थी,कुल सदस्यों में मात्र4-5 प्रतिशत (लगभग 15 महिलाएँ)। यह आँकड़ा दर्शाता है कि प्रारंभिक स्तर पर ही महिलाओं की राजनीतिक उपस्थिति कम थी। इसके बावजूद, संविधान निर्माताओं ने समानता के आदर्शों को अत्यन्त महत्त्व दिया।अनुच्छेद 14विधि के समक्ष समानता औरअनुच्छेद 15लििंग के आधार पर भेदभाव के निषेध की बात करता है। बावजूद इसके अनुच्छेद 15(3) में राज्य को महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति प्रदान की गई। स्पष्ट है कि संवैधानिक स्तर पर महिलाओं के सशक्तिकरण की नींव मजबूत रखी गई थी लेकिन व्यावहारिक राजनीति में यह समानता परिलक्षित नहीं हो

सकी। इस दिशा में पहला वास्तविक और प्रभावी हस्तक्षेप 1992-93 के 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से हुआ। इन संशोधनों ने पंचायतों और नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा देते हुए महिलाओं के लिए कम से कम 33% आरक्षण सुनिश्चित किया। कई राज्यों ने इसे बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक कर दिया।(बिहार सबसे पहला राज्य है जिसने पंचायतों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को बढ़ाकर50% किया, इसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, केरल, ओडिशा और झारखंड जैसे राज्यों ने भी स्थानीय निकायों में 50% महिला आरक्षण लागू किया)। इस प्रयोग ने न केवल महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाया बल्कि यह भी सिद्ध किया कि महिला नेतृत्व शासन को अधिक संवेदनशील, समावेशी और जनकल्याणकारी बना सकता है। यह अनुभव इस बात का ठोस प्रमाण था कि यदि अवसर मिले, तो महिलाएँ प्रभावी राजनीतिक भूमिका निभा सकती हैं। इसके बावजूद, संसद और विधानसभाओं में महिला आरक्षण की राह आसान नहीं रही। 1990 के दशक से लेकर 2010 तक यह विधेयक बार-बार संसद में पेश किया गया।1996, 1998, 1999, 2003 और 2008लेकिन हर बार यह राजनीतिक असहमति के कारण अटक गया। 2010 में राज्यसभा से पारित होने के बावजूद यह लोकसभा में पारित नहीं हो सका। इस विफलता के पीछे कई कारण थेसबसे प्रमुखOBC महिलाओं के लिए अलग उप-कोटा की मांग, पुरुष संसदों का विरोध, और राजनीतिक दलों के बीच सहमति का अभाव। यह स्पष्ट करता है कि महिला प्रतिनिधित्व का प्रश्न केवल सामाजिक न्याय का नहीं, बल्कि सत्ता-साझेदारी का भी प्रश्न है। संवैधानिक व्यवस्था में पहले से ही प्रतिनिधित्व

सुनिश्चित करने के कुछ प्रावधान मौजूद हैं।अनुच्छेद 330 और 332 क्रमशः लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण सुनिश्चित करते हैं, जबकिअनुच्छेद 334इन्हें आरक्षणों की समय-सीमा निर्धारित करता है। महिला आरक्षण अधिनियम, 2023 (106 वें संशोधन) ने इसी ढाँचे को आगे बढ़ाते हुए संविधान मेंअनुच्छेद 330A, 332A और 334A जोड़कर महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया है, हालाँकि, इस अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता और साथ ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी इसका क्रियान्वयन तन्त्र है। अधिनियम के अनुसार, यह आरक्षणजनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही लागू होगा। इस प्रकार एक ओर जहाँ यह ऐतिहासिक कदम है, वहीं दूसरी ओर इसे लागू करने में अनावश्यक विलम्ब किया जा रहा है जिससे इसका प्रभाव कमजोर होने की सम्भावना है। अब सवाल यह है कि अब तक सरकार इसे लागू क्यों नहीं कर पायी है? इसके पीछे कारण है कि जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया लम्बित रही, जिससे क्रियान्वयन टलता गया; अतः संशोधन के माध्यम से इसे 2029 से पहले लागू करने की तैयारी है। इसी कारण विशेष सत्र आहूत हो रहा है। 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए इसमें संशोधन करने की योजना बनाई जा रही है ताकि इसे लम्बित जनगणना से अलग कर समय से लागू किया जा सके। प्रस्ताव के अनुसार लोकसभा की 543 सीटों को बढ़ा कर 816करने और उनमें से 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षितकरने का विचार है। यह आरक्षण वोटकरन मॉडल पर आधारित होगा, जिसमें SC और ST श्रेणियों के भीतर भी महिलाओं को उप-आरक्षण मिलेगा।

चेन्नई के खिलाफ मैच में स्लो ओवर रेट के चलते कार्रवाई, सीजन की पहली गलती केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे पर 12 लाख का जुर्माना

चेन्नई, एजेंसी
IPL 2026 के 22वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को स्लो ओवर रेट की गलती भारी पड़ गई। टीम के कप्तान अजिंक्य रहाणे पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ खेले गए मुकाबले के बाद की गई। यह मैच चेन्नई के ऐतिहासिक एम् ए चिदंबरम स्टेडियम में खेला गया, जहां KKR की टीम निर्धारित समय के भीतर अपने 20 ओवर पूरे नहीं कर सकी। मैच के दौरान ओवर पूरे करने में देरी को लेकर अंपायरों और मैच रेफरी ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन माना। मैच के बाद जारी आधिकारिक बयान में बताया गया कि



IPL की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 के तहत यह KKR का इस सीजन में पहला स्लो ओवर रेट अपराध है। नियमों के मुताबिक, पहली गलती पर कप्तान पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाता है, जो इस मामले में लागू किया गया। हालांकि बोर्ड ने चेतावनी दी है कि यदि टीम दोबारा ऐसी गलती करती है, तो सजा और कड़ी हो सकती है। इसमें कप्तान के साथ-साथ अन्य खिलाड़ियों पर भी आर्थिक दंड लगाया जा सकता है।

अगली बार बढ़ेगी सजा
नियमों के तहत अगर KKR दूसरी बार इस तरह की गलती करती है, तो कप्तान पर 24 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही टीम के अन्य खिलाड़ियों पर उनकी मैच फीस का 25 प्रतिशत या 6 लाख रुपये (जो भी कम हो) का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर तीसरी बार भी टीम स्लो ओवर रेट की दोषी पाई जाती है, तो कप्तान पर 30 लाख रुपये का जुर्माना और एक मैच का प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है।

सीजन के बीच इस तरह की कार्रवाई केकेआर के लिए चेतावनी मानी जा रही है। आगे के मुकाबलों में टीम को अपनी गंदबाजी की गति पर खास ध्यान देना होगा, ताकि दोबारा ऐसी स्थिति न बने और कप्तान पर प्रतिबंध जैसी कड़ी कार्रवाई से बचा जा सके।



चेन्नई ने लगातार दूसरा मैच जीता है।

क्या है स्लो ओवर रेट कानियम?
IPL के नियमों के अनुसार, किसी भी टीम को अपनी गति के 20 ओवर निर्धारित समय—करीब 90 मिनट (जिसमें स्ट्रेटिजिक टाइम-आउट भी शामिल होता है)—के भीतर पूरे करने होते हैं। यदि टीम तय समय से पीछे रह जाती है।

पहला अपराध, इसलिए सीमित सजा
मैच के बाद जारी आधिकारिक बयान में बताया गया कि IPL की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 के तहत यह KKR का इस सीजन में पहला स्लो ओवर रेट अपराध है। नियमों के मुताबिक, पहली गलती पर कप्तान पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाता है, जो इस मामले में लागू किया गया। हालांकि बोर्ड ने चेतावनी दी है कि यदि टीम दोबारा ऐसी गलती करती है, तो सजा और कड़ी हो सकती है। इसमें कप्तान के साथ-साथ अन्य खिलाड़ियों पर भी आर्थिक दंड लगाया जा सकता है।

बार्सिलोना चैंपियंस लीग से बाहर हुई

एटलेटिको मैड्रिड ने 3-2 के एग्रीगेट स्कोर से हराया

नई दिल्ली, एजेंसी
चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल के दूसरे लेग में बार्सिलोना ने एटलेटिको मैड्रिड को 2-1 से हराया, लेकिन कुल स्कोर 3-2 रहने से टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। पहले लेग में एटलेटिको ने 2-0 की जीत हासिल की थी, जो आखिर में निर्णायक साबित हुई। इस जीत की बदौलत वह एग्रीगेट स्कोर पर 3-2 से आगे रही। एटलेटिको मैड्रिड 2017 के बाद पहली बार इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची है। अब आगले दौर में उनका मुकाबला आर्सेनल या स्पॉटिंग लिस्बन में से किसी एक से होगा। मैच के शुरुआती 24 मिनटों में ही बार्सिलोना ने दो गोल कर बहुत बना ली थी। चौथे मिनट में ही युवा खिलाड़ी लेमिन यमल ने गोल कर टीम को बहुत दिला दी। उन्होंने एटलेटिको के डिफेंडर



क्लेमेंट लेगलेट की गलती का फायदा उठाया। इसके बाद 24वें मिनट में फेरान टॉरिस ने दानी ओल्मो के पास पर गोल कर स्कोर 2-0 कर दिया। एक समय ऐसा लग रहा था कि बार्सिलोना आसानी से सेमीफाइनल में पहुंच जायेगी, लेकिन एटलेटिको मैड्रिड ने हार नहीं मानी और मैच में वापसी की। मैच का सबसे अहम मोड़ 31वें मिनट में आया। मार्कोस लोरेटे के पास पर एडमोला लुकमैन ने एटलेटिको के लिए गोल किया। यह गोल एग्रीगेट स्कोर के लिहाज से निर्णायक साबित हुआ।

फास्ट न्यूज

एक्टर ने जबर्दस्ती एक्ट्रेस को बीफ खिलाने की कोशिश की
मुंबई। मलयाली एक्टर और मॉडल शिवाय करीम पर जबर्दस्ती एक्ट्रेस को बीफ खिलाने के आरोप लगे हैं। इस घटना का एक वीडियो भी तैनी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद उनकी जमकर आलोचना भी की जा रही है। एक्टर शिवाय करीम का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो और एक्ट्रेस अनुमोल अनुकृष्णी, एक पार्टी में बुर्फ से खाना लेते नजर आ रहे हैं।

जेल में तेज बुखार में तड़पते रहे विक्रम भट्ट

30 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोप में दिसंबर से फरवरी तक जेल में रहे फिल्ममेकर विक्रम भट्ट ने जेल के दर्दनाक दिनों को याद किया है। फिल्ममेकर की मानें तो उन्हें कड़ाके की ठंड की वजह से तेज बुखार हुआ, वो दर्द से कराह रहे थे, लेकिन वहां मौजूद पुलिसवाले उन्हें डॉक्टर के पास तक नहीं ले गए। जेल के कैदियों ने ही मदद की। ऐसे में वो भगवान से लगातार कहते थे कि वो जेल में नहीं मरना चाहते। विक्रम भट्ट ने जेल के दिनों को याद कर ऑफिशियल सोशल मीडिया से लिखा है, पावर ऑफ प्रेयर्स। उदयपुर जेल में मेरी कैद के लगभग तीन हफ्ते बाद, जनवरी की कड़ाके की ठंड में, एक रात में बेरक नंबर 10 में तेज बुखार के साथ कांपते हुए उठा। चार कंबल ओढ़ने के बाद भी ऐसा लग रहा था जैसे शरीर पर कुछ भी नहीं है। पास में सो रहे कैदियों ने मेरे लिए और कंबल जुटाए। मैंने पैरासिटामोल ली और सोचा कि ठीक हो जाऊंगा।

मार्च में महंगाई दर बढ़कर 3.88% हुई

नई दिल्ली। देश में थोक महंगाई (WPI) लगातार पांचवें महीने बढ़ते हुए मार्च 2026 में 3.88 फीसदी पर पहुंच गई। यह फरवरी के 2.13 फीसदी और पिछले साल मार्च के 2.25 फीसदी से काफी ज्यादा है। बुधवार को जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, इस तेजी के पीछे मुख्य वजह ईंधन, बिजली और मैनुफैक्चरिंग सेक्टर में कीमतों का तेज उछाल है। बेसिक टैट्स, नॉन-फूड आर्टिकल्स और अन्य मैनुफैक्चरिंग उत्पादों की कीमतों में वृद्धि रही।

नागिन 7 में की शूटिंग में टेली प्रॉम्प्टर से डायलॉग पढ़ते दिखे, वीडियो वायरल, जमकर हुए ट्रोल भूत बंगला प्रमोट करने में हुई अक्षय कुमार की किरकिरी



मुंबई। बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म भूत बंगला के प्रमोशन में व्यस्त हैं। इसी सिलसिले में वह टीवी प्रोड्यूसर एकता कपूर के लोकप्रिय सुपरनेचुरल शो नागिन 7 में कैमियो करते नजर आए। हालांकि, शो में उनकी मौजूदगी अब चर्चा से ज्यादा विवाद का विषय बन गई है। गौरतलब है कि अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला 17 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म को एकता कपूर ने अक्षय कुमार के साथ मिलकर को-प्रोड्यूस किया है। यही वजह है कि एक्टर फिल्म के प्रमोशन के लिए उनके टीवी शो में पहुंचे थे। वहीं दूसरे यूजर ने तंज कसते हुए कहा कि इसी वजह से वह



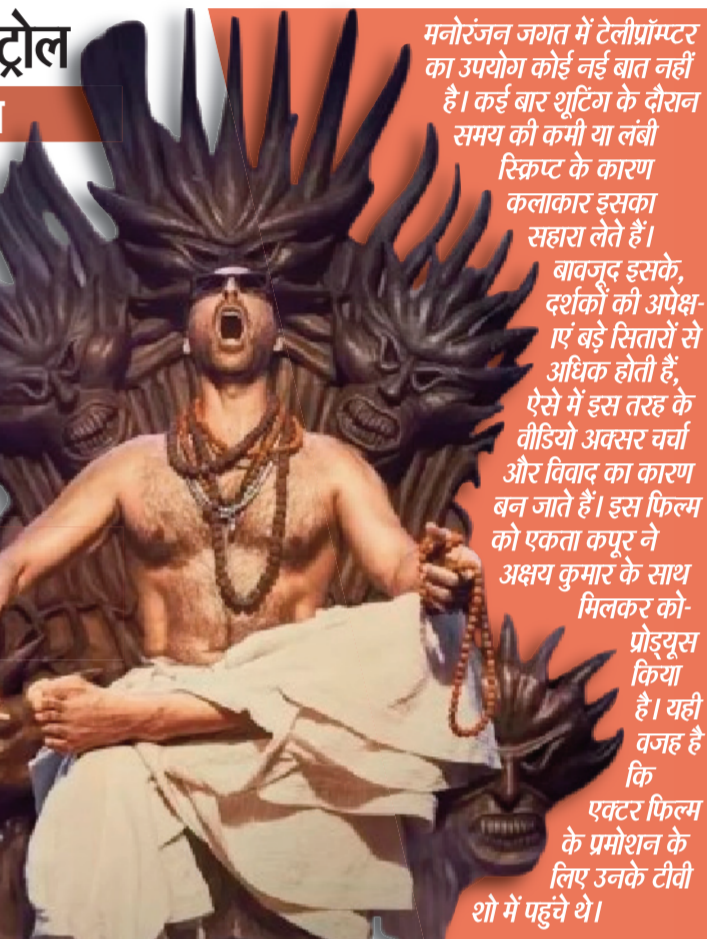
एक साल में कई फिल्में कर लेते हैं। हालांकि कुछ लोगों ने अक्षय का बचाव भी किया। उनका कहना है कि आजकल तेजी से काम करने और समय बचाने के लिए कई कलाकार टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल करते हैं, जो इंडस्ट्री में एक सामान्य प्रक्रिया बन चुकी है।

सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग तेज

वीडियो सामने आने के बाद यूजर्स ने अक्षय कुमार को जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया। एक यूजर ने लिखा कि 30 साल के लंबे करियर के बाद भी अगर 60 साल का एक्टर अपने डायलॉग याद नहीं रख पाता, तो यह हैरान करने वाली बात है। वहीं दूसरे यूजर ने तंज कसते हुए कहा कि इसी वजह से वह एक साल में कई फिल्में कर लेते हैं। हालांकि कुछ लोगों ने अक्षय का बचाव भी किया। उनका कहना है कि आजकल तेजी से काम करने और समय बचाने के लिए कई कलाकार टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल करते हैं, जो इंडस्ट्री में एक सामान्य प्रक्रिया बन चुकी है।

टेलीप्रॉम्प्टर से डायलॉग पढ़ते दिखे अक्षय

वीकेंड पर टेलीकास्ट हुए एपिसोड में अक्षय कुमार ने 'नाग गुरु' के कर्मे में एंटी लेते हुए कैमियो किया। इस दौरान वह शो में नागिन का किरदार निभा रही प्रियंका चहर चौधरी को ड्रैगन यमन से मुकाबला करने की सलाह देते दिखाई दिए। इसी एपिसोड का एक वीडियो क्लिप अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।



मनोरंजन जगत में टेलीप्रॉम्प्टर का उपयोग कोई नई बात नहीं है। कई बार शूटिंग के दौरान समय की कमी या लंबी रिक्वायर्स के कारण कलाकार इसका सहारा लेते हैं। वाजुद इसके दर्शकों की अपेक्षाएं बढ़े रितारों से अधिक होती हैं, ऐसे में इस तरह के वीडियो अक्सर चर्चा और विवाद का कारण बन जाते हैं। इस फिल्म को एकता कपूर ने अक्षय कुमार के साथ मिलकर को-प्रोड्यूस किया है। यही वजह है कि एक्टर फिल्म के प्रमोशन के लिए उनके टीवी शो में पहुंचे थे।

यूके में भारतीय मूल की स्पीच थोक महंगाई 38 महीने में सबसे ज्यादा

एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट बर्खास्त अंग्रेजी न समझ पाने पर नौकरी गई, फॉर्म में गलत जानकारी देने का आरोप

लंदन, एजेंसी

यूके में एक भारतीय मूल की स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट साई कीर्तना श्रीपेरंबुदुर को अंग्रेजी ठीक से न समझ पाने और आवेदन में गलत जानकारी देने के आरोप में नौकरी से निकाल दिया गया। कारण यह रहा कि वह मरीजों और सहकर्मियों की बात ठीक से समझ नहीं पा रही थीं। यह मामला जून 2024 का हो, लेकिन इसकी जानकारी अब सामने आई है। कीर्तना ने अक्टूबर 2023 में यॉर्क एंड स्कारबरो टीचिंग हॉस्पिटल्स NHS ट्रस्ट जॉइन किया था। जॉइनिंग के कुछ ही समय बाद सहकर्मियों को पता चला कि वह नौकरी के साथ-साथ अंग्रेजी सुधारने के लिए क्लास भी ले रही थीं। इस मामले में एक और अहम बात सामने आई कि नौकरी के आवेदन में उन्होंने अंग्रेजी को अपनी 'फर्स्ट लैंग्वेज' बताया था। जबकि फॉर्म के नियमों के अनुसार, 'फर्स्ट लैंग्वेज' वही मानी जाती है जो व्यक्ति रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता हो। केवल अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करना इसे पहली भाषा नहीं बनाता। कीर्तना के मैनेजर ने यह भी बताया कि इंटरव्यू के दौरान उसने चैट बॉक्स के जरिए सवाल पढ़ने का अनुरोध किया था, यानी आमने-सामने बातचीत से बचना चाहती थीं। इसे असामान्य माना गया, खासकर इसलिए क्योंकि वह उस समय यूके में ही रह रही थीं। अस्पताल ट्रस्ट के प्रवक्ता ने पुष्टि की कि साई कीर्तना अक्टूबर 2023 से जून 2024 तक काम पर थीं और जून में उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं। कीर्तना ने इस फैसले को चुनौती दी और कहा कि उनकी पढ़ाई अंग्रेजी में हुई है, इसलिए इसे उनकी पहली भाषा माना जाना चाहिए।



समाप्त कर दी गई। आवेदन में कीर्तना ने अंग्रेजी को अपनी पहली भाषा बताया था, लेकिन बाद में रिज्यू मीटिंग में स्वीकार किया कि उनकी मातृभाषा तेलुगु है। बाद में दिसंबर में उन्होंने बताया कि वह नौकरी के साथ-साथ अंग्रेजी सुधारने के लिए क्लास भी ले रही थीं। इस मामले में एक और अहम बात सामने आई कि नौकरी के आवेदन में उन्होंने अंग्रेजी को अपनी 'फर्स्ट लैंग्वेज' बताया था। जबकि फॉर्म के नियमों के अनुसार, 'फर्स्ट लैंग्वेज' वही मानी जाती है जो व्यक्ति रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता हो। केवल अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करना इसे पहली भाषा नहीं बनाता। कीर्तना के मैनेजर ने यह भी बताया कि इंटरव्यू के दौरान उसने चैट बॉक्स के जरिए सवाल पढ़ने का अनुरोध किया था, यानी आमने-सामने बातचीत से बचना चाहती थीं। इसे असामान्य माना गया, खासकर इसलिए क्योंकि वह उस समय यूके में ही रह रही थीं। अस्पताल ट्रस्ट के प्रवक्ता ने पुष्टि की कि साई कीर्तना अक्टूबर 2023 से जून 2024 तक काम पर थीं और जून में उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं। कीर्तना ने इस फैसले को चुनौती दी और कहा कि उनकी पढ़ाई अंग्रेजी में हुई है, इसलिए इसे उनकी पहली भाषा माना जाना चाहिए।

थोक महंगाई 38 महीने में सबसे ज्यादा

मार्च में ये 3.88% पर पहुंची, रोजाना जरूरत का सामान और फ्यूल महंगा हुआ

नई दिल्ली, एजेंसी

मार्च में थोक महंगाई (WPI) बढ़कर 3.88% पर पहुंच गई है। फरवरी के यह 2.13% पर थी। यानी इसमें एक महीने के अंदर 1.75% की बढ़ोतरी हुई है। थोक महंगाई ने 38 महीने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। जनवरी 2023 में थोक महंगाई 4.73% पर पहुंच गई थी। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने आज यानी 15 अप्रैल को थोक महंगाई के आंकड़े जारी किए हैं। रोजाना की जरूरत वाले सामानों (फ्राइमरी आर्टिकल्स) की महंगाई 3.27% से बढ़कर 6.36% हो गई। खाने-पीने की चीजों (फूड इंडेक्स) की महंगाई में कोई बदलाव नहीं है, ये 1.85% पर बनी हुई है। फ्यूल और पावर की थोक महंगाई दर माइनस 3.78% से बढ़कर 1.05% हो गई है। मैनुफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स की थोक महंगाई दर 2.92% से बढ़कर 3.39% रही। प्राइमरी आर्टिकल, जिसका वेटेज



महंगाई कैसे मापी जाती है?

भारत में दो तरह की महंगाई होती है। एक रिटेल यानी खुदरा और दूसरी थोक महंगाई होती है। रिटेल महंगाई दर आम ग्राहकों की तरफ से दी जाने वाली कीमतों पर आधारित होती है। इसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) भी कहते हैं। वहीं, होलसेल प्राइस इंडेक्स (WPI) का अर्थ उन कीमतों से होता है, जो थोक बाजार में एक कारोबारी दूसरे कारोबारी से वसूलता है। महंगाई मापने के लिए अलग-अलग आइटम्स को शामिल किया जाता है। 22.62% है। फ्यूल एंड पावर का वेटेज 13.15% और मैनुफैक्चर्ड प्रोडक्ट का वेटेज सबसे ज्यादा 64.23% है। प्राइमरी आर्टिकल के भी चार हिस्से हैं। जैसे थोक महंगाई में मैनुफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की हिस्सेदारी

मार्च में रिटेल महंगाई बढ़कर 3.4% पहुंच गई है। इससे पहले फरवरी में यह 3.21% थी। महंगाई में यह बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है जब इजराइल-अमेरिका और ईरान के बीच जंग चल रही है। थोक महंगाई के लंबे समय तक बढ़े रहने से ज्यादातर प्रोडक्ट्स सेक्टर पर इसका बुरा असर पड़ता है।

होलसेल प्राइस इंडेक्स (डब्ल्यूपीआई) का आम आदमी पर असर

आर थोक मूल्य बहुत ज्यादा समय तक ऊंचे स्तर पर रहता है तो प्रोड्यूसर इसका बोझ कंज्यूमर्स पर डाल देते हैं। सरकार टैक्स के जरिए WPI को कंट्रोल कर सकती है। जैसे कच्चे तेल में तेज बढ़ोतरी की स्थिति में सरकार ने ईंधन पर एक्साइज ड्यूटी कटौती की थी। हालांकि, सरकार टैक्स कटौती एक सीमा में ही कम कर सकती है। WPI में ज्यादा वेटेज मेटल, केमिकल, प्लास्टिक, रबर जैसे फैक्ट्री से जुड़े सामानों का होता है। 63.75%, प्राइमरी आर्टिकल जैसे फूड 22.62% और फ्यूल एंड पावर 13.15% होती है। वहीं, रिटेल महंगाई में फूड और प्रोडक्ट की भागीदारी 45.86%, हाउसिंग की 10.07% और फ्यूल सहित अन्य आइटम्स की भी भागीदारी होती है।

सोना ₹2,938 बढ़कर ₹1.53 लाख पर पहुंचा

इस साल कीमत ₹20 हजार बढ़ी, चांदी ₹13,874 महंगी होकर ₹2.51 लाख/किलो हुई

नई दिल्ली, एजेंसी

सोना-चांदी के दाम में आज 15 अप्रैल को तेजी है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 2,938 रुपए बढ़कर 1.53 लाख रुपए पर पहुंच गया है। इससे पहले 13 अप्रैल को इसकी कीमत 1.50 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम थी। वहीं, एक किलो चांदी 13,874 रुपए बढ़कर 2.51 लाख रुपए पर पहुंच गई है। इससे पहले सोमवार को इसकी कीमत 2.37 लाख रुपए प्रति किलो थी। हमेशा यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड (BIS) का हॉलमार्क लगा हुआ सर्टिफाइड गॉल्ड ही खरीदते हैं। ये नंबर अल्ट्रायूमिफिक यानी कुछ इस तरह से हो सकता है- A24524। हॉलमार्किंग से पता चलता है कि सोना कितने कैरेट का है। सोने का सही वजन और खरीदने के दिन उसकी कीमत कई सोसेज (जैसे इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन



की वेबसाइट) से क्रॉस चेक करें। सोने का भाव 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट के हिसाब से अलग-अलग होता है। लेकिन, 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल की ईरान से जंग शुरू होने के बाद गिरावट देखी गई। तब से 47 दिन में सोना 6,148 रुपए और चांदी 15,845 रुपए गिरी है। सोने का भाव उसकी शुद्धता के अनुसार तय होता है। 24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध माना जाता है, जबकि 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने की कीमतें उससे कम होती हैं। बाजार

विदेशी जेवर मंगाने के लिए लाइसेंस लेना होगा

सरकार ने सोने-चांदी और प्लेटिनम के गहनों को 'फ्री' कैटेगरी से हटाकर 'रिस्ट्रिक्टेड' कैटेगरी में डाल दिया है। इसका सीधा असर बाजार की सप्लाय पर दिख रहा है, जिससे सोना-चांदी की कीमतें बढ़ रही हैं। विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, अब इन कीमती धातुओं से बनी ज्वेलरी किसी भी देश से मंगाने के लिए सरकार से विशेष लाइसेंस या परमिशन लेना होगा। सरकार ने यह कदम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए उठाया है।

अलग-अलग शहरों में सोने के दाम अलग होने की 4 वजहें

■ ट्रांसपोर्टेशन और सिक्वोरिटी: एक शहर से दूसरे शहर सोना ले जाने में ईंधन और सुरक्षा खर्च जुड़ता है, जिससे दूरी बढ़ने पर दाम बढ़ते हैं।
■ खरीदारी की मात्रा: दक्षिण भारत में ज्यादा खपत (करीब 40%) के कारण ज्वेलर्स बड़ी खरीद करते हैं, लेकिन शूट का फायदा सीमित रहता है।
■ लोकल ज्वेलरी एसोसिएशन: राज्य और शहर के ज्वेलरी एसोसिएशन स्थानीय मांग-सप्लाय के आधार पर रेट तय करते हैं।
■ पुराना स्टॉक और खरीद मूल्य: ज्वेलर्स का खरीदी रेट तय करता है कि वे ग्राहकों को कितनी कीमत में बेचेंगे।

असली चांदी की पहचान करने के 4 तरीके

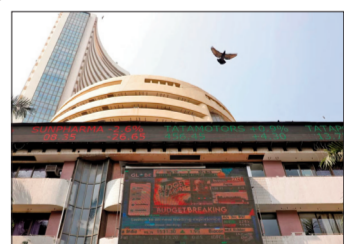
मैनेट टेस्ट: असली सिल्वर चुंबक से नहीं चिपकती। अगर चिपक जाए तो फेक है।
आइस टेस्ट: सिल्वर पर बर्फ रखें। असली सिल्वर पर बर्फ तेजी से पिघलती है।
स्मेल टेस्ट: असली सिल्वर में गंध नहीं होती। फेक में कॉपर जैसी गंध आती है।
क्लॉथ टेस्ट: चांदी को सफेद कपड़े से राइजें। अगर काला निशान आए तो असली है।

सैंसेक्स 1100 अंक चढ़कर 78,000 पर कारोबार कर रहा

निफ्टी भी 350 बढ़कर 24,200 पर पहुंचा, बैंकिंग और ऑटो शेयरों में खरीदारी

नई दिल्ली, एजेंसी

आज यानी बुधवार 15 अप्रैल को सैंसेक्स 1100 अंक (1.48%) की तेजी के साथ 78,000 पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी 350 अंकों (1.35%) की तेजी है, ये 24,200 के स्तर पर आ गया है। आज के कारोबार में ऑटो, आईटी, मेटल और बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में ज्यादा खरीदारी है। सपोर्ट यानी, वह स्तर जहां शेयर या इंडेक्स को नीचे गिरने से सहाया मिलता है। यहां खरीदारी बढ़ने से कीमत आसानी से नीचे नहीं जाती। यहां खरीदारी का मौका हो सकता है। रजिस्टर्ड यानी, वह स्तर जहां शेयर या इंडेक्स को ऊपर जाने में रुकावट आती है। एका बिकवाली बढ़ने से होता है। रजिस्टर्ड स्तर जान करने पर तेजी की उम्मीद रहती है। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने के लिए दूसरे दौर की बातचीत शुरू होने की संभावनाओं ने कच्चे तेल की कीमतों को ठंडा कर दिया है। मंगलवार, 15 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेट कूड



करीब 2.77 डॉलर गिरकर 95.69 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। वहीं, अमेरिकी कूड (WTI) 4 डॉलर की गिरावट के साथ \$95 प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गया है। पिछले सत्र में ईरान जंग के चलते कीमतों में 4.3% तक का उछाल देखा गया था, लेकिन शांति वार्ता की खबरों ने निवेशकों को बड़ी राहत दी है। शेयर बाजार में 13 अप्रैल को गिरावट रही। सैंसेक्स 703 अंक (0.91%) नीचे 76,848 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 208 अंक (1.16%) गिरकर 23,843 पर आ गया। कारोबार में ऑटो और FMCG शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली देखी गई।

